



भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)

प्रलिस के लयः

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), भाखड़ा नांगल बाँध, सधु जल संधा

मेन्स के लयः

सधु जल संधा और संबधति मुद्दे, सरकारी नीतयिँ और हसूतकषेप ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के सदस्योँ के चयन के लयि एक नया मानदंड अपनाने का फैसला कयिा है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नयिमोँ में कयि गए बदलावः

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नयिम, 1974 में संशोधन करने के लयि एक अधसूचना जारी की गई है, जसके तहत बोर्ड के पूरणकालकि सदस्योँ के चयन के मानदंड में बदलाव कयिा गया है ।
 - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नयिम, 1974 के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पॉवर और सचिाई से संबधति स्थायी सदस्य क्रमशः पंजाब तथा हरयिाणा से थे, लेकनि संशोधति नयिमोँ में उनकी स्थायी सदस्यता को हटा दयिा गया है ।
- नए नयिम नयिकूतयिँ के लयि तकनीकी योग्यता का उल्लेख करते हैं और न केवल पंजाब तथा हरयिाणा से बल्कपूरे भारत से सदस्योँ की नयिकूत का मार्ग प्रशसूत करते हैं ।
- नए नयिमोँ का वरिशेध इंजीनयिर व कसिानोँ के साथ-साथ पंजाब के राजनीतकि दलोँ ने भी कयिा है ।
 - इंजीनयिरस का कहना है क शायद ही कोई इंजीनयिर नए वनिरिदेशोँ के अनुसारनयिकूत हेतु अरहता प्रापूत करेगा, ये नयिम पंजाब और हरयिाणा के बाहर से नयिकूत कयि जाने वाले कुछ कर्मयिँ के लयि तैयार कयि गए प्रतीत होते हैं ।
- [REDACTED]

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पतूतः

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पतूत वरूष 1960 में भारत और पाकसूतान के बीच हुई सधु जल संधा में नहिति है ।
 - संधा के तहत तीन पूरवी नदयिँ रावी, ब्यास और सतलुज का पानी वरिशेध उपयोग हेतु भारत को आवंटति कयिा गया, जबकसधु, चनिाब और झेलम नदयिँ का जल पाकसूतान के लयि आवंटति कयिा गया था ।
- भारत में सुनश्चिति सचिाई, बजिली उत्पादन और बाढ़ नयितरण के लयि इन नदयिँ की कषमता का दोहन करने हेतु एक मासूटर प्लान तैयार कयिा गया था ।
 - इस योजना का एक प्रमुख हसूसा भाखड़ा और ब्यास परयिोजनाएँ हैं तथा ततूकालीन अवभाजति पंजाब एवं राजसूथान के संयुक्त उदूयम के रूप में स्थापति की गई थी ।
- 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पुनरूगठन और हरयिाणा राज्य के नरूमाण के बादभाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन पंजाब पुनरूगठन अधनयिम, 1966 की धारा 79 के तहत कयिा गया था ।
- भाखड़ा नांगल परयिोजना का प्रशासन, रखरखाव और संचालन 1 अकूतूबर 1967 को भाखड़ा प्रबंधन को सौंप दयिा गया था ।
- पंजाब पुनरूगठन अधनयिम, 1966 की धारा 80 के प्रावधानोँ के अनुसार, ब्यास परयिोजना कार्य पूरा होने के बादब्यास नरूमाण बोर्ड (BCB) से भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड को स्थानांतरति कर दयिा गया था ।
 - इसके तहत ही भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) कर दयिा गया, जो 15 मई, 1976 को प्रभाव में आया ।
- तब से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) पंजाब, हरयिाणा, राजसूथान, हमाचल प्रदेश, दलिली और चंडीगढ़ के लयि पानी और बजिली की आपूरूत का वनियिमति करता है ।

BBMB का प्रबंधन:

- इसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं जो पंजाब और हरियाणा राज्यों से हैं।
 - उन्हें क्रमशः पंजाब और हरियाणा से वदियुत सदस्य और सचिवाई सदस्य के रूप में नामति कया गया है।
- संबंधति राज्य सरकारों द्वारा नामति सदस्य के साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहति प्रत्येक सदस्य राज्य का प्रतनिधित्व है।
- BBMB में लगभग 12,000 कर्मचारी हैं और इनमें से 696 समूह 'A' के अधिकारी हैं तथा सहयोगी राज्यों में कार्यरत हैं।

ब्यास परियोजना:

- ब्यास-सतलुज लकि योजना में मंडी ज़िले (हिमाचल प्रदेश) में ब्यास नदी पर पंडोह में 76.2 मीटर ऊँचा रॉकफिलि डायवर्ज़न बाँध शामिल है।
- पोंग मुकेरियाँ बाँध, हिमाचल प्रदेश के मुकेरियाँ ज़िले से 40 कमी. दूर ब्यास नदी पर एक बहुउद्देश्यीय पृथ्वी और रॉकफिलि बाँध (Multipurpose Earth & Rockfill Dam) है। यह पंडोह बाँध के नीचे की ओर हिमालय की तलहटी में स्थति है।
- BBMB द्वारा वर्ष 1978-83 से इस परियोजना को कमीशन कया गया।

भाखड़ा नांगल बाँध की विशेषताएँ:

- भाखड़ा बाँध सतलुज नदी पर नरिमति एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बाँध है और उत्तरी भारत में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर नरिमति है।
- यह टहिरी बाँध (261 मीटर) के पास 225.55 मीटर ऊँचा भारत का दूसरा सबसे ऊँचा स्थान है।
- इसका जलाशय, जसि "गोबदि सागर" (**Gobind Sagar**) के नाम से जाना जाता है, 9.34 बलियन क्यूबकि मीटर तक पानी को संग्रहीत करता है।
- नांगल बाँध भाखड़ा बाँध के नीचे नरिमति एक और बाँध है। कभी-कभी दोनों बाँधों को एक साथ भाखड़ा-नांगल बाँध कहा जाता है, हालाँकि ये दो अलग-अलग बाँध हैं।



स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

DIGs की प्रतनियुक्ति

प्रलिमिस के लयि:

उप महानरिीकषक स्तर के आईपीएस अधिकारी, अखलि भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बलों की केंद्रीय प्रतनियुक्ति।

मेन्स के लयि:

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने उप महानरीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतनियुक्ति (Central Deputation) पर एक और आदेश जारी किया है ।

- आदेश में कहा गया है कि DIG स्तर पर केंद्र में आने वाले आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के साथ उस स्तर पर पैनल में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- यह आदेश अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव के बाद आया है जो इसे राज्य की सहमति के साथ या सहमति के बिना केंद्रीय प्रतनियुक्ति पर किसी भी आईपीएस, आईपीएस या आईएफओएस अधिकारी को बुलाने की अनुमति प्रदान करता है ।

प्रमुख बिंदु

मौजूदा आदेश:

- मौजूदा नियमों के अनुसार, डीआईजी-रैंक के आईपीएस अधिकारियों, जिनके पास न्यूनतम 14 साल का कार्य अनुभव है, को केंद्र में प्रतनियुक्ति किया जा सकता है यदि पुलिस स्थापना बोर्ड उन्हें केंद्र में डीआईजी के रूप में सूचीबद्ध करता है ।
 - बोर्ड, अधिकारियों के कार्यकाल और सतर्कता रिकॉर्ड के आधार पर पैनल में उनका चयन करता है ।
 - अभी तक केवल पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को केंद्र के पैनल में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती थी ।
- नया आदेश राज्य में DIG स्तर के अधिकारियों के पूरे पूल को केंद्रीय प्रतनियुक्ति के योग्य बनाता है ।
- हालाँकि यह DIGs को स्वतः ही केंद्र में आने की अनुमति नहीं देगा । अधिकारियों को अभी भी केंद्रीय प्रतनियुक्ति हेतु प्रस्तावित सूची में रखना होगा जो राज्यों और केंद्र द्वारा परामर्श से तय किया जाता है ।

जारी आदेश:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भारी रक्तियों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय प्रतनियुक्ति हेतु DIG स्तर के IPS अधिकारियों के पूल को बढ़ाना है ।
 - वभिन्न CPOs और CAPFs संगठनों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, केंद्र में DIG स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिये आरक्षण 252 पदों में से 118 (लगभग आधे) खाली हैं ।
 - साथ ही यह केंद्र के लिये उपलब्ध अधिकारियों के पूल के आकार को बढ़ाता है ।
- IPS अधिकारियों का CPO और CAPF में 40% का कोटा होता है । केंद्र ने नवंबर 2019 में राज्यों को इस कोटा को 50% कम करने का प्रस्ताव देते हुए लिखा था कि 60% से अधिक पद खाली हैं क्योंकि अधिकांश राज्य अपने अधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं ।
- इसके अलावा MHA ने माना कि है कुछ राज्यों में ज़िलों की संख्या एक दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अधिकारियों की न्युक्ति उस गति से नहीं हुई है ।

राज्यों के समक्ष क्या समस्या है?

- कई राज्यों द्वारा नए आदेश को राज्यों में सेवारत अधिकारियों पर अपनी शक्तियों को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है ।
 - इसके अलावा राज्यों में भी अधिकारियों की गंभीर कमी है ।
- यह सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है ।
- प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर करेगा ।
- यह शासन प्रणाली को प्रभावित करेगा और परहार्य कानूनी एवं प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा ।
- केंद्र एक चुनी हुई राज्य सरकार के खिलाफ नौकरशाही को हथियार बना सकता है ।

अखिल भारतीय सेवाएँ:

- **परिचय:** अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में भारत की तीन सविलि सेवाएँ शामिल हैं:
 - भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
 - भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
 - भारतीय वन सेवा (IFoS) ।
- **अखिल भारतीय सेवाओं की संघीय प्रकृति:** अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा (UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को वभिन्न राज्य संवर्गों के तहत आवंटित किया जाता है ।
 - इसलिये उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदेही होती है ।
 - हालाँकि अखिल भारतीय सेवाओं की केंद्र नियंत्रण अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है ।
 - DoPT भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का केंद्र कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ।
 - भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों (IFoS) की प्रतनियुक्ति के लिये केंद्र कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्रमशः गृह मंत्रालय (MHA) और पर्यावरण मंत्रालय के पास है ।

- **केंद्रीय प्रतनियुक्ति रज़िर्व:** राज्य सरकार को प्रतनियुक्ति हेतु उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतनियुक्ति रज़िर्व (Central Deputation Quota) के तहत नरिधारति करना होता है।
 - प्रत्येक राज्य कैंडर/संवर्ग सेवा का एक केंद्रीय प्रतनियुक्ति कोटा प्रदान करता है जिसके लिये केंद्र सरकार में पदों पर सेवा देने के लिये प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्यों को प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भरती की आवश्यकता होती है।
- **अखलि भारतीय सेवा अधिकारी की प्रतनियुक्ति और वर्तमान नयिम:**
 - सामान्यतः व्यवहार में केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतनियुक्ति (Deputation) पर जाने के इच्छुक अखलि भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है।
 - अधिकारियों को केंद्रीय प्रतनियुक्ति हेतु राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है।
 - राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखलि भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रतनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यत्कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

‘क्लस्टर बम’ और ‘थर्मोबैरकि हथियार’

प्रलिमिस के लिये:

क्लस्टर बम, थर्मोबैरकि हथियार।

मेन्स के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण।

चर्चा में क्यों?

मानवाधिकार समूहों- 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' और 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने रूस पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस द्वारा क्लस्टर बम और 'वैक्यूम बम' का उपयोग किया जा रहा है।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 'क्लस्टर हथियारों' के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। नागरिकों को मारने या घायल करने वाले अंधाधुंध हमले करना एक युद्ध अपराध है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून नयिमों का एक समूह है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमति करना चाहता है। यह उन लोगों की रक्षा करता है, जो युद्ध में हसिसा नहीं ले रहे हैं और साथ ही युद्ध के साधनों एवं तरीकों को भी प्रतबिंधति करता है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री क्या है?

- क्लस्टर युद्ध सामग्री का अर्थ ऐसी 'पारंपरिक युद्ध सामग्री' से है, जसि 20 कलिगग्राम से कम वज़न वाले वसिफोटक सबमशिन के लिये डिज़ाइन किया गया है और इसमें वसिफोटक सबमशिन शामिल हैं।
- क्लस्टर युद्ध सामग्री मूल रूप से ऐसे गैर-सटीक हथियार हैं, जनिहें एक बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध रूप से मनुष्यों को घायल करने या मारने और रनवे, रेलवे या पावर ट्रांसमशिन लाइनों जैसे बुनयिदी ढाँचे को नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है।
- इनहें एक वमिन के माध्यम से गरिया जा सकता है या एक प्रक्षेप्य में लॉन्च किया जा सकता है।
- इनमें से कई बमों में वसिफोट नहीं होता है, लेकिन ये ज़मीन पर पड़े रहते हैं, अक्सर आंशिक रूप से या पूरी तरह से ज़मीन में लुप्त हो जाते हैं और उनका पता लगाना व उनहें नकिलना मुश्कलि होता है, जो लड़ाई बंद होने के बाद लंबे समय तक नागरिक आबादी के लिये खतरा पैदा करते हैं।
- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन वशिष रूप से "क्लस्टर युद्ध सामग्री अवशेष" की पहचान करता है जसिमें "वफिल क्लस्टर युद्ध सामग्री, प्रतियुक्ति क्लस्टर युद्ध सामग्री, गैर-वसिफोटति पनडुबबी और बनिा वसिफोट वाले बम" शामिल हैं।

थर्मोबैरकि हथियार:

- थर्मोबैरकि हथियार (Thermobaric Weapons) जनिहें एरोसोल बम, ईंधन वायु वसिफोटक या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है, एक उच्च तापमान वाले बड़े वसिफोट के लिये वायु से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

- थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी होते हैं।
- ये हथियार, जो कठो अलग-अलग चरणों में होते हैं, टैंक-माउंटेड लॉन्चर से रॉकेट के रूप में दागे जा सकते हैं या वमिन से गरिए जा सकते हैं।
- अपने लक्ष्य को भेदने के दौरान पहला वसिफोट बम के ईंधन कंटेनर को खोल देता है, जसिसे ईंधन और धातु के कणों से बादल (धुआँ का गुबार) का नरिमाण होता है जो एक बड़े कषेत्र में फैल जाता है।
- दूसरा वसिफोट तब होता है जब एयरोसोल कण को आग की एक वशिल गेंद की तरह परज्वलति करता है तथा तीव्र वसिफोट तरंगें भेजता है जो परबलति इमारतों या उपकरणों को भी नषट कर सकता है और मनुष्यों को वाष्पीकृत कर सकता है।

क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन:

- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक कानूनी साधन है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी प्रकार के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण को परतबिधति करता है।
- यह जीवति बचे हुए लोगों और समुदायों को पर्याप्त सहायता, दूषति कषेत्रों से नकिसी, जोखमि में कमी करने की शकिषा एवं भंडार को नषट करने के लयि सहयोग और सहायता हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- वर्ष 2008 में इसे डबलनि, आयरलैंड में अपनाया गया तथा ओसलो, नॉर्वे में हस्ताकषर के लयि खोला गया था। 30 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पूरी होने के बाद यह वर्ष 2010 में लागू कयिा गया।
- वर्तमान में अभसिमय/कन्वेंशन में 110 राज्य दल और 13 हस्ताकषरकर्त्ता देश शामिल हैं।
- कन्वेंशन की पुषटि करने वाले देश क्लस्टर युद्ध सामग्री का उपयोग करने के लयि बाध्य नहीं हैं और न ही वकिसति, उत्पादति, अधग्रहीत क्लस्टर युद्ध सामग्री को स्थानांतरति करने के लयि बाध्य हैं।
- भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताकषर नहीं कयि है और न ही इसका पक्षकार है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकसितान, इजरायल और कुछ अन्य देश इसमें शामिल नहीं हैं।
- वैक्यूम बम (Vacuum Bombs) कसिी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते द्वारा नषिदिध नहीं हैं, लेकनि नरिमाण कषेत्रों, स्कूलों या अस्पतालों तथा नागरकि आबादी के खलिाफ इनका उपयोग वर्ष 1899 और वर्ष 1907 के हेग सम्मेलनों के तहत की गई कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है।
 - हेग कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक शृंखला है जसि वर्ष 1899 और वर्ष 1907 में नीदरलैंड के हेग में आयोजति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से जारी कयिा गया था। यह युद्ध के पारंपरिक नयिमों का सख्ती के साथ अनुपालन तथा उन नयिमों
 - को परभिषति करता है जनिका युद्ध के दौरान युद्धरत पक्षों द्वारा पालन कयिा जाना चाहयि।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सागर परकिरमा

प्रलिमिस के लयि:

सागर परकिरमा, मत्स्यपालन कषेत्र, मत्स्यपालन से संबंधति पहल।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिों और हस्तकषेप, पशुपालन का अर्थशास्त्र, सागर परकिरमा का महत्त्व।

चर्चा में कयों?

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लयि 'सागर परकिरमा' का उद्घाटन करेगा।

सागर परकिरमा:

- यह सभी मछुआरों, मत्स्य कसिानों और संबंधति हतिधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शति करने के लयि पूर्व-नरिधारति समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में आयोजति की जाने वाली एक नेवगिशन यात्रा है।
- इसकी परकिलपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानयिों, नावकिों और मछुआरों का सम्मान करते हुए 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में की गई है।
- परकिरमा पहले चरण में मांडवी, गुजरात से शुरू होगी और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य ज़िलों और अन्य राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में आयोजति की जाएगी।
 - 'सागर परकिरमा' का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च, 2022 को शुरू होगा और 6 मार्च, 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा।
 - रुकमावती नदी मध्य कच्छ ज़िले से नकिलकर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में मलि जाती है।

- गुजरात के कच्छ ज़िले में **अरब सागर** तट के मुहाने पर स्थिति मांडवी से शुरू होकर, जहाँ रुक्मावती नदी कच्छ की खाड़ी से मिलती है, यह पूरी दूरी समुद्री मार्ग से तय की जाएगी।
- रुक्मावती नदी मध्य कच्छ ज़िले से निकलने वाली और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में मलि जाती है।
- इसके तहत तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिये इन स्थानों और ज़िलों में मछुआरों, मछुआरा समुदायों तथा हतिधारकों के साथ बातचीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
- **आत्मनरिभर भारत** के तहत सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हतिधारकों के साथ एकजुटता के लिये समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसकी परिकल्पना की गई है।

महत्त्व:

- यह राष्ट्र की **खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका एवं समुद्री पारस्थितिक तंत्र** की सुरक्षा हेतु समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के साथ स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- महासागर भारतीय तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आजीविका के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।
 - देश में 8118 कमी. की तटरेखा है, जो 9 समुद्री राज्यों/4 केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करती है और लाखों तटीय मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करती है।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र का परदृश्य:

- भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है।
- भारत विश्व में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
- वर्तमान में यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है फरि भी यह अप्रयुक्त क्षमता वाला क्षेत्र है।
- वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मत्स्यपालन क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 से 10.87% की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें 2020-21 के दौरान 145 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हुआ है।
- पछिले 5 वर्षों के दौरान भारतीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 7.53% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश ने वर्ष 2019-20 के दौरान 46,662 करोड़ रुपए (6.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 12.89 लाख मीटरिक टन मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया।
- बुनियादी ढाँचे से संबंधित चुनौतियों के बावजूद हाल के कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपायों ने सुनिश्चित किया है कि मत्स्यपालन क्षेत्र 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को जारी रखे।

मत्स्यपालन से संबंधित पहलें क्या हैं?

- [मत्स्य पालन बंदरगाह](#)
- [समुद्री शैवाल पार्क](#)
- [प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना](#)
- [पाक खाड़ी योजना](#)
- [समुद्री मात्स्यिकी वधियक](#)
- [मत्स्यपालन और एकवाकलचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड \(FIDF\)](#)
- [किसान क्रेडिट कार्ड \(KCC\)](#)
- [समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

डे-लाइट हार्वेस्टिंग

प्रलिमिंस के लिये:

डे-लाइट हार्वेस्टिंग, भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार, भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार पहल।

मेन्स के लिये:

ऊर्जा संरक्षण में डे-लाइट हार्वेस्टिंग का महत्त्व।

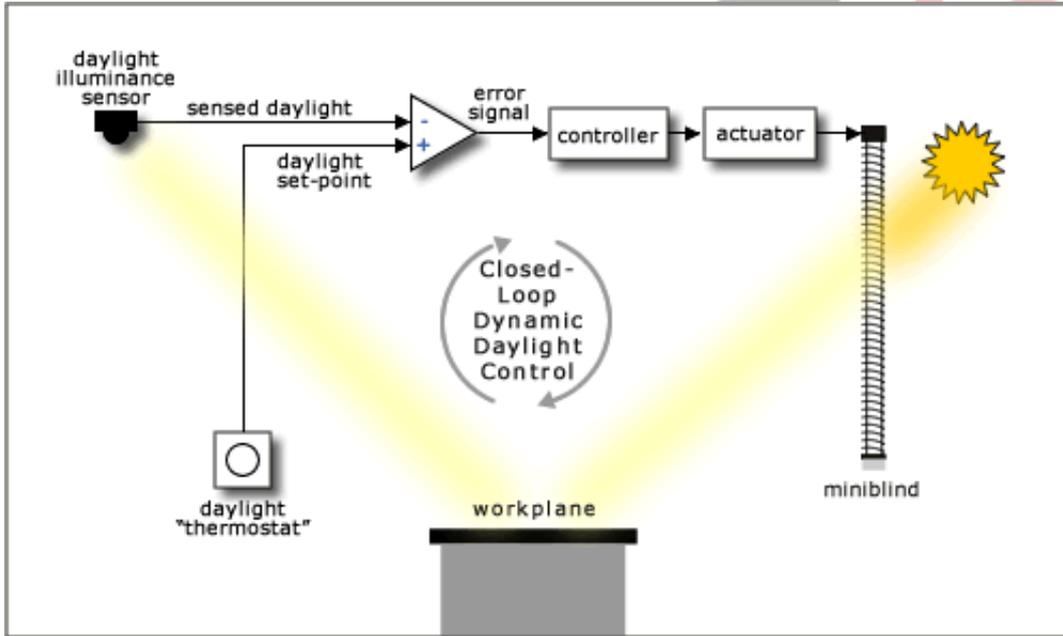
चर्चा में क्यों?

हाल ही में वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने [कार्बन फुटप्रिंट को कम](#) करने और भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिये नवीनतम [डे-लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी](#) में एक अद्वितीय [सटारट-अपस](#) को बढ़ावा देने का नरिणय लया है ।

- मंत्रालय 10 करोड़ रुपए की परयोजना में से 5 करोड़ रुपए 24x7 आधार पर बेसमेंट रोशनी के लयि नई तकनीक वकिसति करने हेतु [स्काईशेड](#) कंपनी को देगा ।
- कंपनी का लक्ष्य हरति भवन का नरिमाण करना तथा [जलवायु परविरतन पर राष्ट्रीय कार्य योजना \(NAPCC\)](#) के तहत राष्ट्रीय मशिनों में भाग लेना व योगदान देना है ।

डे-लाइट हार्वेस्टिंग:

- डे-लाइट हार्वेस्टिंग प्रकाश से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है । यह उपलब्ध सूर्य ऊर्जा का उपयोग करता है ।
 - सौर ऊर्जा स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश के रूप में 45 फीसदी ऊर्जा होती है और इसका उपयोग दनि में लगभग 9-11 घंटे के लयि भवन में रोशनी करने हेतु कया जा सकता है ।
- यह वर्तमान इमारतों के लयि टकिकरू प्रकाश डज़ाइन (Sustainable Lighting Designs) के रूप में उपयोग की जाने वाली सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है ।
- यह अंतरकिष में उपलब्ध प्राकृतिक प्रकाश की मात्रा के स्थान पर प्रकाश की चमक को स्वचालति रूप से कम या समायोजति करता है ।
- खड़िकरिों या रोशनदानों के माध्यम से आने वाले प्राकृतिक दनि के प्रकाश का उपयोग कृत्रमि प्रकाश व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को कम करता है ।
- पर्यावरण में प्रचलति प्रकाश स्तर का पता लगाने हेतु डे-लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक (Daylight Harvesting System) प्रकाश संवेदकों को नयिोजति करती है, जनिहें फोटोकैल सेंसर (Photocell Sensors) के रूप में भी जाना जाता है ।
- यह तब एक नयित्त्रक (Controller) को प्राप्त प्रकाश की तीव्रता भेजता है, जब तक प्रकाश नयित्त्रण प्रणाली से जुड़ा होता है । बदले में नयित्त्रण प्रणाली मापीय प्रकाश स्तर (Measured Light Level) के अनुसार वदियुत रोशनी को स्वचालति रूप से समायोजति करती है ।



‘डे-लाइट हार्वेस्टिंग’ का महत्त्व

- **ऊर्जा की बचत:**
 - यह प्राकृतिक उजाले के आधार पर रोशनी को कम या बंद करके ऊर्जा की बचत को बढ़ाता है ।
- **आराम और सुवधि प्रदान करता है:**
 - यह लगातार एवं स्वचालति रूप से रोशनी को समायोजति करके उचित प्रकाश तीव्रता बनाए रखने में मदद करता है ।
- **स्वस्थ कार्य करने की स्थिति:**
 - लोगों को सही मात्रा में प्रकाश प्रदान करने से उचित ‘सर्कैडियन लय’ बनाए रखने में मदद मिलती है, जो अच्छे स्वास्थ्य और पर्याप्त नींद के लयि महत्त्वपूर्ण हैं, इसके अलावा यह मौसमी उत्तेजति विकारों को रोकने में मददगार है ।
 - ‘सर्कैडियन लय’ 24 घंटे का चक्र है, जो हमारे शरीर को बताता है कि कब सोना है, उठना है और खाना है, यह कई शारीरिक प्रक्रयाओं को नयित्त्रति करता है ।
 - कार्यस्थलों पर प्राकृतिक प्रकाश बेहतर एकाग्रता प्रदान करता है, सकारात्मक मनोदशा बनाता है और स्वस्थ कर्मचारी जीवन को संचालति करता है ।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:**
 - दनि के समय उजाला सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होता है और यह ऊर्जा का एक बहुत ही स्वच्छ एवं लागत प्रभावी स्रोत है ।

- डे-लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करके दान के दौरान हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने से "पंचामृत" के पाँच अमृत की प्रतबिद्धताओं में से एक को सुनिश्चित कर अर्थात् वर्ष 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहल:

- [प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना \(पीएटी\)](#)
- [मानक और लेबलिंग](#)
- [ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता \(ईसीबीसी\)](#)
- [मांग पक्ष परबंधन](#)
- [ईको नविस संहिता](#)
- [ऊर्जा दक्षता ब्यूरो](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

स्थायी संधि आयोग की बैठक

प्रलिस के लिये:

स्थायी संधि आयोग, संधि जल संधि, संधि और इसकी सहायक नदियाँ।

मेन्स के लिये:

संधि जल संधि और संबंधित मुद्दे, संधि जल संधि का इतिहास और भारत-पाकसिान संबंधों पर इसका प्रभाव, भारत-पाकसिान संबंध।

चर्चा में क्यों?

भारत और पाकसिान के बीच 'स्थायी संधि आयोग' (PIC) की 117वीं बैठक आयोजित की गई।

- इससे पहले केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास परबंधन बोर्ड (BBMB) के सदस्यों के चयन के लिये नए मानदंड अपनाने का फैसला किया था।

बैठक की मुख्य वशिषताएँ:

- दोनों पक्षों ने जल विज्ञान और बाढ़ के आँकड़ों के आदान-प्रदान पर चर्चा की, जिसके दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी सभी परियोजनाएँ संधि जल संधि के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।
- 'फाजलिका नाले' के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और पाकसिान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजलिका नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
 - 'फाजलिका नाला' उन 22 नालों और जलाशयों में से एक है, जहाँ मालवा ज़िले (पंजाब, भारत) का अनुपचारित पानी छोड़ा जाता है।
 - देशों की सीमा रेखा पर नाला बंद है, जिससे तालाबों में ठहराव आ जाता है और सीमावर्ती क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- पाकल दुल, करि और लोअर कलनई जैसी परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी चर्चा भी की गई।
 - पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1000 मेगावाट) केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी की एक सहायक नदी 'मरुसुदर' पर प्रस्तावित है।
 - जम्मू-कश्मीर के कश्तिवाड़ ज़िले में स्थित चिनाब नदी पर करि जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) प्रस्तावित है।
 - लोअर कलनई परियोजना 'जम्मू-कश्मीर' के डोडा और कश्तिवाड़ ज़िलों में एक पनबजली परियोजना है।
- भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया कि एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भारत संधि के तहत अनविरय रूप से प्रतविरष जलाशयों से पानी के निरवहन और बाढ़ प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता रहा है।

संधि जल संधि का इतिहास क्या है?

- संधि नदी बेसिन में छह नदियाँ हैं- संधि, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज; जो कतिबिबत से निकलती हैं तथा हिमालय पर्वतमाला से बहती हुई पाकसिान में प्रवेश करती हैं और अंततः अरब सागर में मलि जाती हैं।
- वर्ष 1947 में भारत और पाकसिान के लिये भौगोलिक सीमाओं को चिह्नित करने के अलावा विभाजन की रेखा ने संधि नदी प्रणाली को भी दो भागों में

बाँट दिया था।

- चूँकि दोनों पक्ष अपने सचिवाई बुनियादी ढाँचे को क्रियाशील रखने के लिये सधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर थे, इसलिये इस नदी के जल को समान रूप से वभाजित किया गया।
- प्रारंभ में मई, 1948 के अंतर-प्रभुत्व समझौते को अपनाया गया था, जिसमें दोनों देशों ने एक सम्मेलन के लिये सहमती व्यक्त की जिसके बाद फैसला किया कि भारत पाकिस्तान द्वारा किये गए वार्षिक भुगतान के बदले में पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति करेगा।
 - हालाँकि यह समझौता जल्द ही विघटित हो गया क्योंकि दोनों देश इसकी सामान्य व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सके।
- वर्ष 1951 में इस जल-बँटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सचिवाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये विश्व बैंक में आवेदन किया व विश्व बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की।
- अंततः 1960 में विश्व बैंक द्वारा लगभग एक दशक की तथ्य-खोज, बातचीत, प्रस्तावों और उनमें संशोधन के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ तथा सधु जल संधि (IWT) पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किये गए।

The Indus Waters Treaty (IWT)

■ The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).

■ Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after eight years of negotiations.

■ Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.

Western rivers

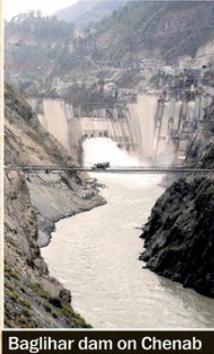
Chenab, Jhelum, Indus

India's rights over these rivers: Limited — can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions

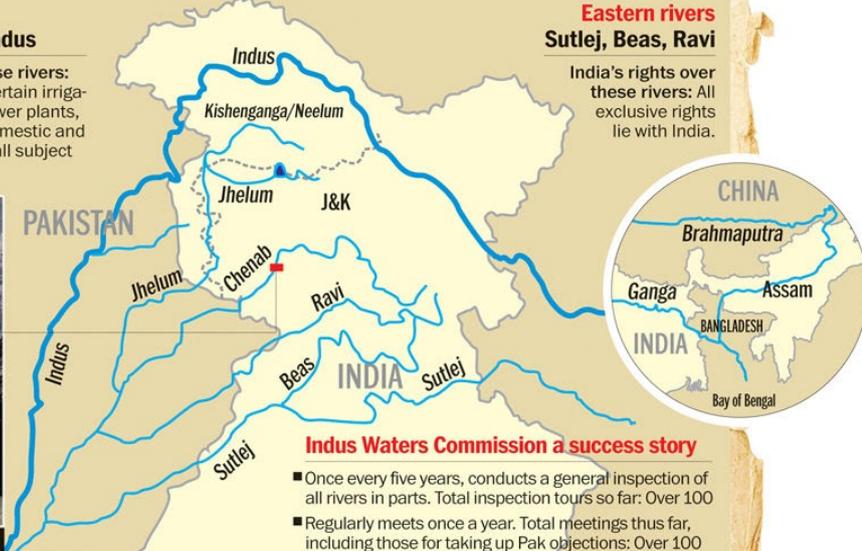
Eastern rivers

Sutlej, Beas, Ravi

India's rights over these rivers: All exclusive rights lie with India.



Baglihar dam on Chenab



Indus Waters Commission a success story

- Once every five years, conducts a general inspection of all rivers in parts. Total inspection tours so far: Over 100
- Regularly meets once a year. Total meetings thus far, including those for taking up Pak objections: Over 100

प्रमुख प्रावधान:

■ साझा जल:

- संधि ने निर्धारित किया कि सधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सधु, चिनाब और झेलम को अप्रतबंधित जल उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतबंधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया था।
 - इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 33 MAF या 20% जल भारत के उपयोग के लिये छोड़ दिया गया।

■ स्थायी सधु आयोग:

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।

■ नदियों पर अधिकार:

- जबकि झेलम, चिनाब और सधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।

■ डज़ाइन संबंधी वनिरिदेश:

- यह कुछ डज़ाइन वनिरिदेश भी प्रदान करता है जिनका भारत को ऐसी परियोजनाओं को वकिसति करते समय पालन करना होता है।

■ आपत्तियाँ उठाना:

- यह संधि पाकिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्तियाँ उठाने की भी अनुमति देती है, अगर वह उन्हें वनिरिदेशों के अनुरूप नहीं पाता है।
- भारत को परियोजना के डज़ाइन या उसमें किये गए परिवर्तनों के बारे में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी है, जैसे प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर आपत्तियाँ, यदि कोई हो, के साथ जवाब देना आवश्यक है।
- इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर रखने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिये 3.75 एमएएफ पानी तक स्टोर कर सकता है।

■ वविाद समाधान तंत्र:

- IWT तीन चरणों वाला वविाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।
- जल-बँटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष नरिणय लेने के लिये तटस्थ वशिषज्ज (NE) की नयुक्त हेतु वशिष बैंक से संपर्क कर सकता है।
 - और अंततः यदिकोई भी पक्ष पूर्वोत्तर के नरिणय से संतुष्ट नहीं है तो संधिभामलों की व्याख्या और सीमा "वविाद" से संबंधित मामला मध्यस्थता न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है।

भू-राजनीतिक संघर्षों के बारे में:

- हाल के वर्षों में भारत और पाकसिातान के बीच भू-राजनीतिक तनाव के दौरान सधु जल संधिको कई बार चर्चा में लाया गया है।
- वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सैन्य शविरि पर हमले के बाद भारत ने कहा किरक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते ("Blood and Water cannot flow simultaneously)" जिसके तुरंत बाद भारतीय पक्ष द्वारा स्थायी सधु आयोग की वारता उस वर्ष के लिये नलिंबति कर दी गई, जिसने एक बटु पर संधिसे बाहर निकलने की धमकी भी दी थी।
- वर्ष 2019 में जब पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ और जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई, भारत ने पहली बार सधु नदी प्रणाली से पाकसिातान को पानी की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी।
- बाद में यह स्पष्ट किया गया कि पाकसिातान की आपूर्तिको प्रतबिंधित करना आईडब्ल्यूटी (IWT) का उल्लंघन होगा तथा केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के वचिर की आवश्यकता होगी।
 - IWT के पास कोई एकतरफा नकिस प्रावधान नहीं है और इसे तब तक लागू रहना चाहयि जब तक कदिनों देश एक और पारस्परिक रूप से सहमत समझौते की पुष्टि नहीं करते।

स्थायी सधु आयोग:

- यह भारत और पाकसिातान के अधिकारियों का एक द्वपिक्षीय आयोग है, जिसे सधु जल संधि (वर्ष 1960) के कार्यान्वयन एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था।
- सधु जल संधिके अनुसार, आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमति तौर पर भारत और पाकसिातान में बैठक करेगा।
- आयोग के नमिनलखिति कार्य हैं:
 - नदियों के जल से संबंधित दोनों देशों की सरकारों की कसिी भी समस्या का अध्ययन करना और दोनों सरकारों को रपिरट देना।
 - जल बँटवारे को लेकर उत्पन्न वविादों का समाधान करना।
 - प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार नदियों का नरिीक्षण करने हेतु सामान्य दौरा करना।
 - संधिके प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

स्रोत: द हट्टि

युद्ध अपराध

प्रलिमिस के लयि:

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, युद्ध अपराध, 1949 जनिवा कन्वेंशन।

मेन्स के लयि:

महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, यूक्रेन पर रूस का युद्ध, युद्ध अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय कानून।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने घोषणा की है कविह यूक्रेन में रूस द्वारा कयि गए संभावति युद्ध अपराधों की जाँच शुरू करेगा। युद्ध अपराधों के लयि वशिषिट अंतरराष्ट्रीय मानक मौजूद हैं।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय:

- ICC, हेग (नीदरलैंड्स) में स्थिति एक स्थायी न्यायिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 1998 के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संवधि (इसकी स्थापना और संचालन संबंधी दस्तावेज़) द्वारा किया गया था और 1 जुलाई, 2002 को इस संवधि के लागू होने के साथ ही इसने कार्य करना प्रारंभ किया।
- **मुख्यालय:** हेग, नीदरलैंड
- **सदस्य:**
 - 123 राष्ट्र रोम संवधि के पक्षकार हैं और आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत सदस्य नहीं हैं।
- रोम संवधि ICC को चार मुख्य अपराधों पर क़्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
 - नरसंहार का अपराध
 - मानवता के वरिद्ध अपराध
 - युद्ध अपराध
 - आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression)

युद्ध अपराध:

- युद्ध अपराधों को संघर्ष के दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- ICC की रोम संवधि द्वारा स्थापित परिभाषा, 1949 जनिवा अभिसमयों से ली गई है।
- यह इस विचार पर आधारित है कि वियक्तियों को किसी राज्य या उसकी सेना के कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **बंधक बनाना, जान-बूझकर हत्या करना, युद्धबंदियों के साथ अत्याचार या अमानवीय व्यवहार तथा बच्चों को लड़ने** के लिये मजबूर करना आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।

जनिवा कन्वेंशन (1949)

- **जनिवा कन्वेंशन (1949)** तथा इसके **अन्य प्रोटोकॉल** वे अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमिति करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं।
- ये संधियाँ/प्रोटोकॉल उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, जैसे- **नागरिक, सहायता कार्यकर्त्ता** तथा जो युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते जैसे- **घायल, बीमार और जहाज़ पर सवार सैनिक एवं युद्धबंदी**।
 - पहला जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान **घायल एवं बीमार सैनिकों** को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - दूसरा जनिवा कन्वेंशन, युद्ध के दौरान **समुद्र में घायल, बीमार एवं जहाज़ पर मौजूद सैन्यकर्मियों** को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - तीसरा जनिवा कन्वेंशन, **युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर लागू** होता है।
 - चौथा जनिवा कन्वेंशन, कब्ज़े वाले क़्षेत्र सहित **नागरिकों को संरक्षण** प्रदान करता है।
- भारत **जनिवा कन्वेंशन** का एक पक्षकार है।

युद्ध अपराधों के लिये मानदंड:

- **मानदंड:** यह तय करने के लिये कि क्या किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून तीन सदिधांतों को निर्धारित करता है:
 - **भेद:** उन उद्देश्यों को लक्षित करना अवैध है, जिनसे "नागरिकों के जीवन को आकस्मिक नुकसान तथा नागरिकों को चोट लगना, नागरिक उद्देश्यों को नुकसान पहुँचाने की आशंका होती है, जो कि अनुमानित टोस और प्रत्यक्ष सैन्य लाभ के संबंध में अधिक होता है।
 - **अनुपातकिता:** अनुपातकिता सेनाओं को अत्यधिक हिसा वाले हमले का जवाब देने से रोकती है।
 - उदाहरण के लिये यदि एक सैनिक मारा जाता है तो इसके प्रतिशोध में आप पूरे शहर पर बमबारी नहीं कर सकते।
 - **एहतियात:** यह संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के लिये नागरिक आबादी को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु उपाय करना या नुकसान को कम-से-कम करना अनिवार्य बनाता है।
- **परिभाषा में अस्पष्टता:** शहरों या गाँवों पर छापेमारी, आवासीय भवनों या स्कूलों पर बमबारी और यहाँ तक कि नागरिकों के समूहों की हत्या भी तब 'युद्ध अपराध' नहीं होता जब यह सैन्य अभियान के दृष्टिकोण से उचित हो।
 - हालाँकि यही कार्य तब 'युद्ध अपराध' बन सकते हैं यदि इनके परिणामस्वरूप अनावश्यक वनिाश, पीड़ा और लोग हताहत होते हैं, जो कि सैन्य अभियान के दौरान आवश्यक नहीं था।
 - इसके अलावा नागरिक और सैन्य आबादी में अंतर करना कठिन होता है।

'युद्ध अपराध' और 'मानवता के वरिद्ध अपराध' में अंतर:

- नरसंहार की रोकथाम और सुरक्षा उत्तरदायित्व पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (या नरसंहार कन्वेंशन) युद्ध अपराधों को नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराधों से अलग करता है।
- युद्ध अपराधों को घरेलू संघर्ष या दो राज्यों के बीच युद्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- जबकि नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध शांतकाल में या नहित्थे लोगों के समूह के प्रति सेना की एकतरफा आक्रामकता के दौरान हो सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/04-03-2022/print>

